उठाते हैं तो जिस राज्य में ये परियोजनाएं चलायी जाती हैं उस राज्य की यह मांग निरंतर रहती है कि हमारे क्षेत्र में ये परियोजाएं चलायी जा रही हैं उसका लाभ अन्य राज्य उठाते हैं ....

श्री सभापति : आप इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : उसी का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए यह 12 प्रतिशत की बात तय हो गयी और परंपरा के तहत यह 12 प्रतिशत की बात निरंतर चलती आ रही है। अब कुछ राज्य 12 प्रतिशत से बढ़ाकर ज्यादा मुफ्त बिजली मांगने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : ठीक है। प्रश्न संख्या 123

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

*123. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ इन आंकड़ों की तुलना किस तरह की जा सकती है ?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी खपत के लिए पृथक श्रेणीकरण नहीं किया जाता है। भारत में कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति लगभग 30% सूचित की गयी है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति लगभग 21% अनुमानित की गयी है।

(ग) भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत विकासशील देशों और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की तलना में कम है। तथापि, भारत की प्रति व्यक्ति खपत पड़ोसी देशों अर्थात्

पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार की तुलना में अधिक है। वर्ष 1999 के लिए कुछेक विकासशील और विकसित देशों में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश का नाम	वर्ष 1999 के दौरान विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत
ब्राजील	1874
मिश्र	960
चीन	936
यू. के.	5902
आस्ट्रेलिया	9908
यू. एस. ए.	13451
पाकिस्तान	337.78
बांग्लादेश	95.24
श्रीलंका	258.55
नेपाल	48.75
म्यांमार	79
भारत	364

विवरण

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत

राज्य/यूटी का नाम	उपभोग (कि०वा०घं०)
हरियाणा	529.03
हिमाचल प्रदेश	340.55
जम्मू व कश्मीर	269.33
पंजाब	924.11
राजस्थान	339.80
उत्तर प्रदेश	177.03
चण्डीगढ़	821.66
दिल्ली	646.23
गुजरात	838.39
मध्य प्रदेश	353.13

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत—जारी

राज्य/यूटी का नाम	उपभोग (कि०वा०घं०)
महाराष्ट्र	573.62
गोवा	724.92
दमन और दीव	3927.36
दादरा व नगर हवेली	3691.63
आंध्र प्रदेश	426.43
कर्नाटक	368.48
केरल	315.03
तमिलनाडु	549.71
पांडिचेरी	1149.94
लक्षद्वीप	244.57
बिहार	146.73
उड़ीसा	336.67
पश्चिम बंगाल	207.32
अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	219.87
सिक्किम	192.38
असम	101.20
मणिपुर	69.50
मेघालय	161.02
नागालैंड	83.25
त्रिपुरा	95.48
अरुणाचल प्रदेश	68.60
मिजोरम	121.03
अखिल भारत	**363.90**

Per Capita Consumption of Electricity

†*123. JANESHWAR MISHRA : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) the details of State-wise per capita consumption of electricity in the country;

(b) the details of consumption of electricity in urban and rural areas of various States of the country; and

(c) how these compare with international data in this regard ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The details of State-wise per capita consumption of electricity in the country during the year 1999-2000 are given in the enclosed statement *(See* below).

(b) Separate classification for rural and urban consumption is not maintained by the State Electricity Boards/Utilities. Supply of power to agricultural consumers in India is reported to be approx. 30%. The supply to domestic consumers is estimated to be approx. 21%.

(c) Per capita consumption in India is lower as compared with the per capita consumption of electricity in developing countries as well as developed countries. However, per capita consumption of India is higher as compared to neighbouring countries *i.e.* Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Myanmar. The details of per capita consumption of electricity in some of the developing and developed countries for the year 1999 are given below :—

Name of the country	Per Capita consumption of electricity during 1999 (in Kwh.)
Brazil	1874
Egypt	960
China	936
U.K.	5902
Australia	9908
U.S.A.	13451
Pakistan	337.78
Bangladesh	95.24
Sri Lanka	258.55
Nepal	48.75
Myanmar	79
India	364

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

State-wise per Capita consumption for the year 1999-2000

Name of State/UTs	Consumption (Kwh)
Haryana	529.03
Himachal Pradesh	340.55
Jammu and Kashmir	269.33
Punjab	924.11
Rajasthan	339.80
Uttar Pradesh	177.03
Chandigarh	821.66
Delhi	646.23
Gujarat	838.39
Madhya Pradesh	353.13
Maharashtra	573.62
Goa	724.92
Daman and Diu	3927.36
D and N Haveli	3691.63
Andhra Pradesh	426.43
Karnataka	368.48
Kerala	315.03
Tamil Nadu	549.71
Pondicherry	1149.94
Lakshadweep	244.57
Bihar	146.73
Orissa	336.67
West Bengal	207.32
A and N Islands	219.87
Sikkim	192.38
Assam	101.20
Manipur	69.50
Meghalaya	161.02
Nagaland	83.25
Tripura	95.48
Arunachal Pradesh	68.60
Mizoram	121.03
All India	**363.90**

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, हमने अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि राज्यवार पर-कैपिटा बिजली की खपत क्या है ? सरकार ने जवाब दिया है कि राज्य विद्युत बोर्डों ने इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं दी और राज्यवार कोई भी रिपोर्ट शहर और गांवों के हिसाब से नहीं मिली है। मेरा ख्याल है कि मेरे सवाल का यह जवाब नहीं है।

दूसरा, इन्होंने अपने जवाब में ही कहा है कि भारत में कृषि उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति लगभग 30 सैकड़ा सूचित की गयी है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति लगभग 21 सैकड़ा अनुमानित की गयी है। अब इससे यह सवाल उठता है कि देश में बिजली का संकट सभी राज्यों में भयानक है। कई बार तो गांवों में जाने पर 15-20 दिनों तक बिजली नहीं मिलती है। गांवों के किसान जिनको बिजली सवेरे 6 घंटा आजकल जाड़े में दी जा रही है—2.00 बजे से लेकर 8.00 बजे तक, 8.00 बजे के बाद खत्म कर दी जाती है जैसे कि गांव का किसान केवल खेत में काम करता है और खेत में काम करने वाला अन्न पैदा करने वाला एक जानवर है, उसकी कोई मानवीय जिंदगी नहीं है, उसके बच्चे पढ़ते नहीं हैं ···

श्री सभापति : मिश्र जी, मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था लेकिन आप जो सप्लीमेंट्री कर रहे हैं वह आपके इस प्रश्न के स्कोप से बाहर है ··· **(व्यवधान)** ··· आपने खुद कहा है कि प्रति व्यक्ति कितनी खपत है। यह आपका प्रश्न है।

श्री जनेश्वर मिश्र : नहीं सर, वह तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि ···

श्री सभापति : नहीं दिया है ··· **(व्यवधान)** आपने कहा है गांवों में बिजली कब मिल रही है, शहरों में कब मिल रही है ··· **(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र : इन्होंने यह कहा है कि भारत में कृषि उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति लगभग 30 सैकड़ा सूचित की गयी है। इस पर हमें यह कहना है कि यह राज्य सरकारों को निर्देश दें तो केन्द्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाएगा और वह नहीं देंगे। क्या मंत्री जी सूचित करेंगे कि ऐसे समय जब उन के बच्चों की पढ़ाई होती हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गांवों के किसानों को बिजली दी जाय केवल सिंचाई की दृष्टि से नहीं बल्कि उपभोक्ता की दृष्टि से। अगर यह ऐसा नहीं कर सकते तो इनको मैं किसान विरोधी कहूंगा।

श्री सभापति : लेकिन आप यह बताइए कि यह विषय राज्य सरकार का है, राज्य बिजली बोर्ड का है या केन्द्र सरकार का है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह राज्य बिजली बोर्ड का है।

श्री सभापति : तो वहां पूछ लेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, यह उस को निर्देश तो कर सकते हैं क्योंकि पूरे देशभर के लिए बिजली तो यही गाइड करते हैं और अगर यह राज्य का विषय है तो यह सवाल ही एडमिट नहीं होना चाहिए था।

श्री सभापति : यह बात सही है।

श्री जनेश्वर मिश्र : दूसरी बात, दुनिया के और देशों के मुकाबले में भारत की पर-कैपिटा बिजली की खपत क्या है ? यह तो राज्य का विषय नहीं है। सभापति महोदय, मुझे कहना पड़ रहा है कि एक तरफ इन्होंने जवाब दिया है कि अमेरिका में पर कैपिटा 13451 यूनिट की खपत है और हिंदुस्तान में 364 यूनिट की खपत है। सभापति महोदय, हम यह तो नहीं कहते कि भारत एक दिन में अमेरिका बन जाय, लेकिन मिश्र जैसे दूसरे देश जहां 6 सौ, 7 सौ और 8 सौ यूनिट की खपत कर रहे हैं, आप का टार्गेट कब तक का है ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, वही उनका मूल प्रश्न है और मूल प्रश्न के उत्तर में हमने यह सारी बातें बता दी हैं।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, हमारे देश में जो पर-कैपिटा कंजंप्शन है, वह 364 यूनिट का है और जो बात माननीय सदस्य ने कही, विद्युत वितरण की पूरी जिम्मेदारी शत-प्रतिशत राज्यों की है।

श्री सभापति : हो गया।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी भी है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार किया कि अब गांवों के किसानों पर, खेती करने वाले किसानों से बिजली का टैक्स वसूल किया जाएगा, कई किसान संगठनों ने सरकारों को इस तरह का ज्ञापन दिया है कि खेती की सिंचाई के लिए जो बिजली शुल्क लेने का प्रावधान हो, इसको समाप्त किया जाय और माफ किया जाए। क्या सरकार विचार कर रही है कि गांवों के किसानों पर से खेती पर लगाए जाने वाले शुल्क, जिस की तजवीज आई है, वह मॉफ रहेगा ?

श्री सभापति : मुझे क्षमा करेंगे, यह इस प्रश्न के स्कोप के बाहर है।

DR. ARUN KUMAR SARMA : Sir, the reply of the Hon. Minister indicates that in the State of Assam, the power consumption is as low as only 101 units. I want to know precisely from the Hon. Minister, whether it is due to lack of adequate generation of power or due to lack of adequate distribution network. Sir, why I am saying this is because in the North-East, the water flow is more than 33 per cent and 67 per cent in the rest of the country, and it is a very good source for hydro-power by which more than 55,000 megawatts of power can be produced and can be supplied to the entire Northern belt of the country. Now, I want to know : What is the status of generation of power from various hydro-power projects ? So many other projects are under consideration of the Government, including the NHPC-1 and Subansiri Dam Project. Till now, they have not yet been commissioned. They are yet to be commissioned. My question is : What is the present state of affairs ?

MR. CHAIRMAN : If you want to reply, you can.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सर, मैंने पहले ही प्रश्न में स्पष्ट किया है कि वितरण राज्य का विषय है। जहां तक खपत का सवाल है, यह ऊर्जा निर्माण से सीधा संबंधित नहीं है। ऊर्जा निर्मिती होने के बावजूद यदि राज्य सरकारें या विद्युत बोर्ड इसका वितरण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं या सब स्टेशन नहीं लगा सकते हैं तो यह खपत का प्रमाण वह दे सकते हैं।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। श्री सन्तोष बागड़ोदिया । ··· (**व्यवधान**) ···

श्री संतोष बागड़ोदिया : धन्यवाद, सभापति जी। दस दिन के बाद मौका मिला है, फिर भी यह लोग मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। एनी वे, कोई बात नहीं। यह जो कन्जम्पशन की बात मंत्री महोदय ने कही है कि यह कन्जम्पशन पर कैपिटा है। लेकिन, इतनी चोरी होती है 50 परसेंट तक, तो कन्जम्पशन की फिगर के अलावा आप मुझे यह बता दें कि पर कैपिटा प्रोडक्शन कितनी है तो उससे ज्यादा पता लगेगा क्योंकि ज्यादा तो चोरी हो रही है, कन्जम्पशन तो हो रहा है और इससे आपकी यह कन्जम्पशन की फिगर बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है, क्योंकि 50 परसेंट चोरी हो रही है, टी. डी. लोसेस हो रहे हैं। कन्जम्पशन की फिगर तो आपने दे दीं कि इतनी कन्जम्पशन होती है, लेकिन उसमें हमको सही नहीं मिलती है।

श्री सभापति : बागड़ोदिया जी, यह कन्जम्पशन का प्रश्न नहीं है, उत्पादन का प्रश्न है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, कन्जम्पशन की फिगर गलत है और वह इसलिए गलत है, जैसा मैंने कहा कि रास्ते में जो चोरी हो जाती है उसको इन्होंने कन्जम्पशन में काउण्ट ही नहीं किया है। जब प्रोडक्शन हुआ, रास्ते में जो उससे चोरी हुआ तो वह चोरी वाला भी तो किसी ने कन्ज्यूम किया है। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ।

श्री सभापति : जी, आप दूसरा सवाल कर लीजिए। यह इसमें नहीं आता।

श्री संतोष बागड़ोदिया : कोई बात नहीं, सर। मैं आपकी रूलिंग को मानता हूँ। मेरा दूसरा सवाल मंत्री महोदय से यह है कि यह जो कन्जम्पशन है 364, यह ऑल इंडिया की है, तो इसमें क्या आपने कम से कम डवलपिंग कंट्रीज के अनुसार कोई टाइम लिमिट बनाया है कि एक वर्ष में, दो वर्ष में, तीन वर्ष में कितनी-कितनी कन्जम्पशन बढ़ेगी? हर साल कन्जम्पशन कितनी बढ़ेगी? आपने कोई फिगर ऐसी बनाई हैं या अंदाज से जब बढ़ जाएंगी तब आप बता देंगे। हर साल की एक फिगर होती है। तो मंत्री महोदय बताएंगे कि अगले तीन साल में पर कैपिटा कन्जम्पशन कितनी-कितनी बढ़ेगी?

श्री सभापति : इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। ह्युमन रिसोर्स डवलपमेंट की रिपोर्ट भी पढ़ लें तो उसमें भी है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें तो मिलती नहीं।

श्री सभापति : मेरे से आप ले लीजिए।